दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स राजस्थान

मई (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में राजस्थान बना अग्रणी 3
- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन 3
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 4
- 'मियाँ का बाड़ा' रेलवे स्टेशन, अब कहलाएगा महेश नगर हॉल्ट 4
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 2021 : कोटा विश्वविद्यालय ने जीता पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक 4
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3 नवीन तहसील और 1 उप-तहसील खोलने के प्रस्ताव को दी मंज़ूरी 5
- नवीन सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ 5
- इन्वेस्ट राजस्थान, 2022 6
- 12वीं सीनियर नेशनल वुमन हॉकी चैंपियनशिप, 2022 6
- राजस्थान मनरेगा के विभिन्न मानकों पर देश भर में प्रथम 6
- राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2022 7
- राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय 7
- राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति 8
- राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, 2022 8
- राजस्थान निक्षय संबल योजना 9
- 'चुप्पी तोड़ो-सयानी बनो' अभियान 9
- देश का 52वाँ टाइगर रिज़र्व बना रामगढ़ विषधारी अभयारण्य 10
- राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में विकसित किये जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब 11
- जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का प्रयास 11
- तंबाकू नियंत्रण का 'राजस्थान मॉडल' 11
- राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल 12
- राज ओलिव स्टोर 12
- राज्य के सभी ज़िलों में बनाई जाएंगी लव-कुश वाटिकाएँ 13
- आरएसएलडीसी का 'सीएक्सओ कॉन्क्लेव' 13
- मुख्यमंत्री ने ई-ह्वीकल पॉलिसी को मंज़ूरी दी 13
- राजीविका की महिलाओं के जैविक उत्पादों का होगा प्रमाणीकरण 14
- कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 में संशोधन 14
- राज्यपाल ने किया 'शिखर पर्व' का शुभारंभ एवं 'हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी' का लोकार्पण 15
- मोरध्वज की नगरी को बनाया जाएगा पर्यटन नगरी 15
- एसएमएस स्टेडियम में लोकार्पण व खिलाड़ी सम्मान समारोह 16
- जैसलमेर में भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू 16
- नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के प्रस्ताव को मंज़ूरी 17

नोट :

राजस्थान

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में राजस्थान बना अग्रणी

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में श्री सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल, राजकोट एवं अहमदाबाद द्वारा आयोजित मेगा फ्री हार्ट कैंप का उद्घाटन करते हुए कहा कि यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू करने वाला राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 34 लाख परिवार जुड़ चुके हैं तथा किडनी, हार्ट, लीवर, बोनमेरो ट्रांसप्लांट जैसे महँगे इलाज़ भी इस योजना में नि:शुल्क किये जा रहे हैं।
- सभी अस्पतालों में आईपीडी एवं ओपीडी मरीजों के लिये नि:शुल्क उपचार व नि:शुल्क एमआरआई, एक्स-रे तथा सीटी स्कैन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेशवासियों को इलाज के खर्च से चिंतामुक्त करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' एवं 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान' जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ शुरू की हैं।
- उन्होंने कहा कि सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल के साथ किये गए एमओयू के तहत 314 हृदय रोग से पीड़ित बच्चों और अन्य लोगों की नि:शुल्क सर्जरी की गई है। सरकार द्वारा बच्चों को गुजरात आने एवं जाने के लिये 5 हज़ार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
- यह अस्पताल हार्ट ऑपरेशन जैसे महँगे ऑपरेशन नि:शुल्क कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री अस्पताल से ठीक होकर आए बच्चों से मिले तथा बीमार बच्चों से मिलकर उन्हें नि:शुल्क हार्ट सर्जरी का टोकन दिया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना में 5 हज़ार से अधिक दवाईयाँ, सर्जिकल्स एवं सूचर्स सूचीबद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही सभी अस्पतालों में बिना किसी खर्च के पूरा इलाज़ कैशलेस करने की व्यवस्था की गई है।
- वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले, सामाजिक-आर्थिक जनगणना, 2011 में चिह्नित नागरिक, संविदाकर्मी, लघु और सीमांत किसान तथा कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले सभी परिवारों का बीमा प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा भरा जा रहा है तथा अन्य सभी परिवार बीमा प्रीमियम की आधी राशि देकर योजना से जुड़ सकते हैं।

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मोबाइल एटीएम वेन का अवलोकन कर पहला ट्रांजेक्शन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक को नाबार्ड के सहयोग से कुल 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई हैं। ये मोबाइल एटीएम वैन बैंक सेवा क्षेत्र के सभी ज़िलों में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं ढ़ाणियों में आमजन को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करेंगी।
- इसके साथ ही सीमा पर तैनात सैनिकों को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाने का कार्य भी इन वैनों के द्वारा किया जाएगा।
- मोबाइल एटीएम वैनों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरुकता के लिये शिविर आयोजित कर आमजन को बैंकिंग के बारे में जागरूक किया जाएगा व सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाई जाएगी।

नोट :

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2022 को राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना' की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर पाँच लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा।
- बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ व एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा तथा दुर्घटना में हाथ पैर आँख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा।
- योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

'मियाँ का बाड़ा' रेलवे स्टेशन, अब कहलाएगा महेश नगर हॉल्ट

चर्चा में क्यों ?

30 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी में राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के बालोतरा इलाके में स्थित 'मियाँ का बाड़ा' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'महेश नगर हॉल्ट' कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- इससे पहले 2018 में इस गाँव का नाम बदलकर मियाँ का बाड़ा से महेश नगर किया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला जा सका था। यह गाँव पाकिस्तान के सीमावर्ती बाड़मेर ज़िले की समदड़ी तहसील में आता है।
- उल्लेखनीय है कि 2018 में राजस्थान के तीन गाँवों के नाम तत्कालीन भाजपा सरकार ने बदले थे। इसमें मियाँ का बाड़ा गाँव का नाम बदलकर महेश नगर, इस्माइल खुर्द का नाम नाम बदलकर पिचनवा खुर्द और नरपाड़ा को नरपुरा किया गया था।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 2021 : कोटा विश्वविद्यालय ने जीता पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों ?

3 मई, 2022 को बंगलुरू में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 2021 में पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान) ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय (हरियाणा) को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- कोटा विश्वविद्यालय ने बढ़त बनाते हुए अपनी विरोधी टीम को ऑल आउट होने पर मज़बूर कर दिया और 15 अंकों के अंतर से जीत हासिल कर खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया।
- वहीं महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (हरियाणा) ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (हरियाणा) को हराकर खिताब जीता।
- उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु में 24 अप्रैल से 3 मई, 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 2021 का आयोजन किया गया।

नोट :

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत युवा छात्रों को विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेने और उन्हें खेलने के लिये प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन 31 जनवरी, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वर्ष 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3 नवीन तहसील और 1 उप-तहसील खोलने के प्रस्ताव को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

4 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिये 3 नवीन तहसील और 1 उप-तहसील खोलने के प्रशासनिक प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार जोधपुर में तीन नवीन तहसीलें- झँवर, कुड़ी भगतासनी और घंटियाली तथा प्रतापगढ़ में एक नवीन उप-तहसील मूंगाणा का सृजन किया जाएगा।
- जोधपुर ज़िले में नवीन तहसील झँवर कार्यालय और पटवार मंडलों, भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्तों के सृजन करने के लिये स्वीकृति मिली है। झँवर के क्षेत्राधिकार में 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 14 पटवार मंडल एवं 79 राजस्व ग्राम शामिल हो रहे हैं।
- जोधपुर ज़िले की उप-तहसील कुड़ी भगतासनी को नवीन तहसील और उप-तहसील घंटियाली को नवीन तहसील के रूप में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
- कुड़ी भगतासनी के क्षेत्राधिकार में 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 11 पटवार मंडल एवं 24 राजस्व ग्राम शामिल हो रहे हैं। वहीं घंटियाली के क्षेत्राधिकार में 5 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 17 पटवार मंडल और 46 राजस्व ग्राम शामिल किये गए हैं।
- इसी तरह मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ ज़िले में नवीन उप-तहसील मूंगाणा के सृजन के प्रशासनिक प्रस्ताव को भी मंज़ूरी प्रदान की है। इसके क्षेत्राधिकार में 4 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त (1 पूर्ण व 3 आंशिक), 9 पटवार मंडल एवं 45 राजस्व ग्राम शामिल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र 2022-23 के दौरान वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान बिंदु संख्या 86 में नवीन कार्यालय सृजन की घोषणा की गई थी।

नवीन सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

5 मई, 2022 को राजस्थान राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नवीन सिलिकोसिस पोर्टल, 2022 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने बताया कि राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति के अंतर्गत सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को व्यवस्थित और सरलता से प्रदान करने हेतु ऑटो अप्रूवल आधारित इस पोर्टल को शुरु किया गया है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि पोर्टल को सर्वप्रथम पायलट स्तर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, टोंक, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं बाराँ ज़िलों में प्रारंभ किया गया है।
- नवीन सिलिकोसिस पोर्टल के माध्यम से अब सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता राशि ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरण की जा सकेगी।

नोट :

इन्वेस्ट राजस्थान, 2022

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर 'इन्वेस्ट राजस्थान, 2022' की तैयारियों की समीक्षा बैठक संबोधित की।

प्रमुख बिंदु

- 'इन्वेस्ट राजस्थान, 2022' का आयोजन जयपुर के सीतापुरा स्थित 'जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर' में 7 और 8 अक्टूबर, 2022 को होगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के लिये देश भर में रोड शो और इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किये गए। इनमें 10.45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिये 4192 एमओयू एवं एलओआई हुए है, जिनसे प्रदेश में 9.69 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- उद्योग एवं वाणिज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के कनेक्ट कार्यक्रमों की श्रृंखला में जयपुर में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जेट्रो) के समन्वय से गोल्फ इवेंट, विशाखापत्तनम् के मेडिकल डिवाइस पार्क, वडोदरा के पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंवेस्टमेंट रीजन (पीसीपीआईआर) और गुरुग्राम के फिनटेक पार्क में रोड शो आयोजित किये जाएंगे।

12वीं सीनियर नेशनल वुमन हॉकी चैंपियनशिप, 2022

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2022 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल में 12वीं सीनियर नेशनल वुमन हॉकी चैंपियनशिप, 2022 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस चैंपियनशिप में मेजबान मध्य प्रदेश सहित देश की 27 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें चंडीगढ़, बिहार, हरियाणा, असम, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पुदुच्चेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोआ, गुजरात, केरल, तेलंगाना, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश की टीमें शामिल हैं।
- चैंपियनशिप में इन टीमों को 8 पूलों में बांटा गया है। पूल-ए में मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार, पूल-बी में हरियाणा, असम, बंगाल शामिल हैं।
- पूल-सी में पंजाब, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा तथा पूल-डी में महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं।
- झारखंड, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी को पूल-ई में रखा गया है, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार को पूल-एफ में रखा गया है।
- पूल-जी में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोआ और गुजरात, पूल-एच में ओडिशा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है।
- 12वीं सीनियर नेशनल वुमन हॉकी चैंपियनशिप, 2022 का फाइनल मैच 17 मई को खेला जाएगा।

राजस्थान मनरेगा के विभिन्न मानकों पर देश भर में प्रथम

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि मनरेगा में अनुमोदित श्रम बजट, 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या, मानव दिवसों के सृजन तथा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिक दर तेज़ी से बढ़ी है। मनरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिवस का अतिरिक्त रोज़गार दिया जा रहा है।

नोट :

- वहीं सहरिया, खैरुआ, कथौड़ी व विशेष योग्यजन को राज्य सरकार द्वारा 100 दिन का अतिरिक्त रोज़गार देने के आदेश भी जारी हो चुके हैं।
- भीषण गर्मी को देखते हुए मनरेगाकर्मियों के लिये कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, क्रेच, मेडिकल किट, साबुन-सेनेटाइज़र आदि की व्यवस्था करवाई गई है।
- गाँवों के लिये मास्टर प्लान बनाकर वहाँ शहरों की तर्ज पर ढाँचागत सुविधाओं को विकसित करने की योजना के तहत डांग, मेवात व मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड की राशि को बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है।
- मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से चयनित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी विकास पथ का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों का चयन होगा।
- प्रदेश में 50,000 फॉर्म पौंड, डिग्गी व टैंकों का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बंजर भूमि व चरागाह विकास बोर्ड द्वारा 1000 चरागाह तैयार किया जाएगा।
- प्रदेश में 50,000 स्वयं सहायता समूह के गठन की कार्ययोजना बनाई गई है, जिससे 5.50 लाख ग्रामीण महिलाएँ लाभान्वित होंगी।
- इन स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड व कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी व बैंक ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।
- महिला को-ऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा जयपुर में खोली जाएगी, साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में मेट व्यवस्था के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक महिला मेटों के नियोजन का कार्य किया जा रहा है। भीलवाड़ा ज़िले में 100 प्रतिशत महिला मेट का नियोजन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2022

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2022 को जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र पर आयोजित दस दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2022 का समापन हो गया। इसकी शुरूआत 30 अप्रैल को हुई थी।

प्रमुख बिंदु

- इस मेले में कारोबार एवं डिसप्ले की दृष्टि से समितियों को पुरस्कृत किया गया है। इनमें बिक्री के आधार पर शीर्ष संस्थाओं में प्रथम स्थान पर कॉनफैड, द्वितीय स्थान पर तिलम संघ व तृतीय स्थान पर जयपुर डेयरी रहा।
- क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में प्रथम स्थान भीनमाल, दूसरा स्थान मथानिया एवं तीसरा स्थान आबूरोड का रहा। इसी तरह से ज़िला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में कोटा, उदयपुर व जोधपुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- सर्वश्रेष्ठ डिसप्ले के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में कृभको, इफको तथा शीर्ष सहकारी संस्थाओं में राजफैड, कॉनफैड, तिलम संघ, जयपुर डेयरी एवं अपैक्स बैंक को सम्मानित किया गया।
- राज्य विशेष के विशिष्ट उत्पादों एवं मसालों की बिक्री एवं प्रदर्शन हेतु मार्केटफैड केरल, इरोड, पंजाब, टैनफैड तमिलनाडु की सहकारी संस्थाओं को सम्मानित किया गया।
- ज़िला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में उदयपुर, श्रीगंगानगर व कोटा क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार केवीएसएस की श्रेणी में नागौर, आबूरोड एवं जोधपुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिये नियमों में आवश्यक संशोधन को मंज़ूरी समेत एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये समान पात्रता परीक्षा आयोजित कराने जैसे कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बैठक में 1 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात् नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
- इससे 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे।
- 31 मार्च, 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रैल, 2022 से देय होंगे।
- प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किये जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे- ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर अब समान पात्रता परीक्षा (CTET) आयोजित होगी। इसके लिये राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 बनाया जाएगा।
- बजट 2022-23 की घोषणा के अनुरूप राजस्थान के निवासी पैरालंपिक पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नि:शुल्क 25 बीघा भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया है।
- जैसलमेर ज़िले में 6,000 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि को 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिये राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं अडानी समूह के मध्य करार से स्थापित संयुक्त उपक्रम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को कीमतन भूमि आवंटन पर निर्णय किया गया है।
- इसके अलावा जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ में कुल रकबा 290.62 हैक्टेयर राजकीय भूमि को ईडन रिन्यूएबल पैसी प्राइवेट लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय किया है। इस निर्णय से 150 मेगावॉट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हो सकेगी।

राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु

- इन पदक विजेता खिलाड़ियों में से 46 को लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर, 14 को वनपाल के पद पर, 3 को आबकारी रक्षक के पद पर तथा 2 को कांस्टेबल के पद पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान की गई है।
- प्रस्ताव के अनुसार, इन राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर रूल्स, 2017 के तहत उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार आनुपातिक रूप से विभागों का आवंटन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ-साथ स्नातकोत्तर या स्नातक की योग्यता रखते हैं, उन्हें उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार शासन सचिवालय तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्ति दी गई है।
- मुख्यमंत्री की इस मंज़ूरी से खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में कार्य करने के साथ-साथ अपनी खेल गतिविधियों को सुचारु रूप से जारी रखने में आसानी होगी।

राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, 2022

चर्चा में क्यों ?

12 मई, 2022 को राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्त्वावधान में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, 2022 के आयोजन के तहत जयपुर से रोड शो की शुरुआत की गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आरडीटीएम) पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिये बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकों की सुविधा को एक मंच प्रदान करने की अनूठी पहल है।
- उल्लेखनीय है कि 6 अप्रैल, 2022 को पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म राजस्थान के बीच राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के आयोजन के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- आरडीटीएम को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन विभाग द्वारा कई नवाचारों, जैसे- राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2022 गेस्ट हाउस स्कीम, संशोधित होमस्टे (पीजी) स्कीम सहित रोड शो का आयोजन किया जा रहा है।
- पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म राजस्थान के संयुक्त तत्त्वावधान में 22-24 जुलाई, 2022 को जयपुर में आरडीटीएम के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा।
- इस आयोजन से पहले होटल व्यवसायियों, ट्रेवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों को आमंत्रित करने के लिये विभिन्न शहरों में रोड शो किये जाएंगे। इन रोड शो का उद्देश्य राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है।
- ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और व्यापार संघों से समर्थन से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर), इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशंस (आरएटीओ) भी शामिल हैं।

राजस्थान निक्षय संबल योजना

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2022 को राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा जन-सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 'राजस्थान निक्षय संबल योजना' का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य क्षय अनुभाग द्वारा स्वास्थ्य भवन के सभागार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी की अध्यक्षता में राज्य टीबी फोरम की बैठक में इस योजना का शुभारंभ किया गया।
- इस अवसर पर शासन सचिव डॉ. पृथ्वी ने 'राजस्थान निक्षय संबल योजना' के पोस्टर का विमोचन भी किया।
- बैठक में डॉ. पृथ्वी ने राज्य के सभी उद्योगों, कॉर्पोरेट संस्थानों, जन प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि से टीबी रोगियों और उनके परिवारों को पोषण, रोज़गारोन्मुखी एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने के कार्य में सहयोग करने और टीबीमुक्त प्रदेश बनाने में अपनी सामाजिक भागीदारी निभाने की अपील की।
- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सामूहिक भागीदारी पर विशेष बल दिया। उन्होंने सभी टीबी रोगियों की एचआईवी एवं डायबिटीज की जाँच करने के निर्देश भी दिये।
- जन-स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. वी.के. माथुर ने कहा कि विभाग द्वारा राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर पूर्व उपचारित रोगियों को टीबी चैंपियन के रूप में चिह्नित किया जा रहा है, जो क्षय रोगियों की समस्याओं के निदान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- टीबी चैंपियन समुदाय में क्षय रोगियों की आवाज़ बनेंगे और विभाग द्वारा 'निक्षय पोषण योजना' के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जा रही सहायता राशि दिलाने में भी सहयोग करेंगे।

'चुप्पी तोड़ो-सयानी बनो' अभियान

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2022 को जयपुर ज़िला कलेक्टर राजन विशाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय गणगौरी बाज़ार में 'चुप्पी तोड़ो-सयानी बनो' अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ज़िला कलेक्टर ने बताया कि नागौर और अलवर ज़िले के बाद जयपुर में इस अभियान की शुरुआत की गई है।
- 'चुप्पी तोड़ो-सयानी बनो' अभियान के तहत ज़िले के 929 विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग एक लाख 30 हज़ार किशोरी बालिकाओं द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं द्वारा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई।
- कार्यशाला में राज्य सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत बालिकाओं को सैनेटरी नैपकीन नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई। अभियान के तहत कार्यशाला में प्रत्येक छात्रा को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर बुकलेट व प्रत्येक राजकीय विद्यालय में 'गुड टच बैड टच' विषय पर पोस्टर एवं बैनर उपलब्ध करवाए गए।
- ज़िले में कक्षा 9 से 12वीं तक चयनित 3 हज़ार 716 बालिकाओं को हाईजीन एंबेसडर नियुक्त किया गया है। ये बालिकाएँ विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ ही अभिभावकों, जन-प्रतिनिधि, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, एएनएम, साथिन, आशा सहयोगिनी एवं विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाओं को भी जागरूक करेंगी।
- उल्लेखनीय है कि अभियान के द्वितीय चरण से पहले जयपुर ज़िले के प्रत्येक उपखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यशाला, प्रशिक्षण, जन-जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन चरणबद्ध रूप से किया गया।
- इस अभियान के प्रथम चरण में राजकीय विद्यालय में कार्यरत् 2 हज़ार 223 अध्यापिकाओं को 14 से 16 मार्च तक प्रशिक्षण दिया गया था।

देश का 52वाँ टाइगर रिज़र्व बना रामगढ़ विषधारी अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि राजस्थान के बूंदी ज़िले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वाँ टाइगर रिज़र्व घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- अधिसूचना के बाद रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिज़र्व बन गया है। मौज़ूदा समय में राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व हैं।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अंतर्गत 5 जुलाई, 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिज़र्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- एनटीसीए द्वारा प्रदान की गई, स्वीकृति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व के क्रिटिकल टाइगर हैबीटैट (कोर) एवं बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
- इस समिति द्वारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व, ज़िला बूंदी के कोर तथा बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु 24 जनवरी, 2022 को राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- उल्लेखनीय है कि नए अधिसूचित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व में पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिज़र्व और दक्षिण की तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के बीच बाघों का अधिवास शामिल है।
- राजस्थान सरकार ने इसे 20 मई, 1982 को राजस्थान वन्य प्राणी और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 की धारा 5 के अंतर्गत अभयारण्य घोषित किया था।
- यह अभयारण्य बाघ संरक्षण के अलावा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ पुष्प प्रजातियों के लिये भी खासा प्रसिद्ध है। अभयारण्य में भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, चीतल, सांभर, सुस्त भालू, गोल्डन जैकल, चिंकारा, नीलगाय, लोमड़ी, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर, सांप, मगरमच्छ सहित 500 प्रकार के वन्यजीव मौज़ूद हैं।

नोट :

राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में विकसित किये जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2022 को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान के प्रत्येक ज़िले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये 'डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब' विकसित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का उद्देश्य ज़िला स्तर के उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना है, ताकि छोटे उद्योगों को मदद मिल सके और वे स्थानीय लोगों को रोज़गार के मौके उपलब्ध करवा सकें।
- इसके प्रथम चरण में जयपुर और जोधपुर ज़िलों को चुना गया है। बाद में चरणबद्ध तरीके से इसमें सभी ज़िलों को शामिल किया जाएगा।
- इसी संदर्भ में ज़िला उद्योग केंद्र, जयपुर (शहर) में बैठक आयोजित की गई और शहर के लिये जेम्स एंड ज्वैलरी तथा जयपुर ग्रामीण के लिये ब्लू पॉटरी के विकास पर चर्चा की गई।

जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का प्रयास

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये गठित पुनर्वास बोर्ड की बैठक में जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिये चरणबद्ध तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा कि रेस्क्यू किये गए भिखारियों को विभाग द्वारा संचालित पुनर्वास गृह में 7 दिन पुनर्वासित कर चिह्नित किया जाए और उन्हें पात्रता अनुसार बाल गृह, नारी निकेतन, मानसिक विमंदित गृह, वृद्धाश्रम गृह आदि में भेजने तथा प्रशिक्षण में रुचि रखने वाले भिक्षावृत्ति में लिप्त एवं निर्धन व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रेस्क्यू किये जाने वाले भिखारियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने के साथ ही चिह्नित व्यक्तियों के पुन: भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए जाने पर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।
- गौरतलब है कि राजस्थान में भिखारियों का पुनर्वास करने के लिये 'राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012' को क्रियान्वित किया जा रहा है।

तंबाकू नियंत्रण का 'राजस्थान मॉडल'

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2022 को भारत सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोटपा, 2003 के प्रावधानों को लागू करने हेतु राजस्थान सरकार की तर्ज़ पर विशेष अभियान चलाने और तंबाकू नियंत्रण के संबंध में 'राजस्थान मॉडल'का पालन करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर फरवरी 2022 में 100 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया था, जिसका समापन 31 मई, 2022 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस (डब्ल्यूएनटीडी) पर होगा।
- इस 100 दिवसीय विशेष अभियान में गाँव से लेकर राज्य स्तर तक तंबाकू नियंत्रण पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। राज्य भर के गाँवों में स्कूलों में वाद-विवाद, चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को 31 मई को राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

नोट :

- इसके अलावा अभियान में राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वाले 9.83 लाख से अधिक लोगों को 1 मई से एक मेगा ड्राइव शुरू करके कोटपा, 2003 के तहत दंडित किया गया है।
- राज्य स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक ने कहा कि राज्य में तंबाकू की खपत में लगभग 8% की कमी आई है।
- उल्लेखनीय है कि 2003 में व्यापक तंबाकू नियंत्रण कानून [सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम - सीओटीपीए, 2003] बनाया गया, जिसका उद्देश्य धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना और तंबाकू के विज्ञापन व प्रचार पर प्रतिबंध लगाना है।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 (2019-21) के अनुसार किसी भी प्रकार के तंबाकू (15 वर्ष और अधिक) का उपयोग करने वाले पुरुषों की संख्या 42% है, जबकि एनएफएचएस-4 (2015-16) में यह 46.9% है।

राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल

चर्चा में क्यों ?

20 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के राजस्थान चेप्टर की ओर से आयोजित 'राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल'का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहरों को आगामी 20-25 वर्षों की आवश्यकता के अनुरूप नियोजित करने के लिये वास्तुविदों और नगर नियोजकों का पैनल तैयार किया गया है।
- राजस्थान ऐसा राज्य है, जिसने सभी नगरों के मास्टर प्लान और राज्य के लिये आधुनिक बिल्डिंग बाय-लॉज तैयार किये हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1972 में संसद से वास्तुविद् अधिनियम पारित कराकर और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रसिद्ध वास्तुविद् और नगर नियोजक चार्ल्स कोरिया को महत्त्व देकर देश के नगरीय विकास की मज़बूत नींव रखी थी।
- जयपुर में कला एवं संस्कृति को आमजन तक पहुँचाने के लिये जवाहर कला केंद्र भवन का डिज़ाइन कार्य भी चार्ल्स कोरिया ने ही किया था।
- समारोह में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांती कुमार धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से ही जयपुर परकोटा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है।

राज ओलिव स्टोर

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2022 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर के दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिसर में 'राज ओलिव स्टोर'का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह स्टोर जैविक सब्जियाँ और विभिन्न ओलिव उत्पाद की आम जनता के लिये उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खोला गया है।
- इसके अतिरिक्त स्टोर में शुद्ध पानी और जैविक सब्जियों के साथ जैतून से बने उच्च ग्रेड शहद, तेल और सिरका भी उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं।
- इस स्टोर में सब्जियों की आपूर्ति कृषि विभाग के बस्सी स्थित कृषि उत्कृष्टता केंद्र से की जाती है।
- गौरतलब है कि ऑलिव ऑयल विभिन्न पोषक तत्त्वों का एक बड़ा स्रोत है। इसमें विटामिन ए, डी, ई और के के अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अल्फा लिनोलिक एसिड, ओलेइक एसिड और ओमेगा-9 फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो कैंसर, दिल संबंधी बीमारी, हडिन्यों से जुड़े रोग, डायबिटीज आदि में लाभदायक है।

नोट :

राज्य के सभी ज़िलों में बनाई जाएंगी लव-कुश वाटिकाएँ

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य में ईको-टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक ज़िले में लव-कुश वाटिका विकसित करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- प्रत्येक ज़िले में लव-कुश वाटिका विकसित करने में लगभग 2-2 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- मुख्यमंत्री ने वन अधिकारियों को वाटिकाओं में वन एवं वन्यजीवों से संबंधित ऐसे मॉडल स्थापित करने के निर्देश दिये, जिनसे बच्चों को पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण की शिक्षा मिल सके।
- मुख्यमंत्री ने सभी घोषणाओं को समय पर सुनियोजित तरीके से पूरा कराने, वन क्षेत्र में वन्यजीवों से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिये सख्त कदम उठाने तथा अभयारण्य घूमने आने वाले पर्यटकों को वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिये।
- उन्होंने चूरू के तालछापर अभ्यारण्य में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र की प्रगति, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने, जोधपुर में 'पँश्री कैलाश सांखला स्मृति वन' को शुरू करने, फतेहपुर-सीकर में सिटी नेचर पार्क के निर्माण सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की।
- बैठक में प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्री शिखर अग्रवाल ने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध के लिये आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

आरएसएलडीसी का 'सीएक्सओ कॉन्क्लेव'

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2022 को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) की ओर से 'सीएक्सओ कॉन्क्लेव' का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप ट्रेंड कर रोज़गार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने पर मंथन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- आरएसएलडीसी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. आरुषी मलिक ने प्रदेश में मौजूद युवा कार्यबल को ताकत बताते हुए कहा कि युवाओं को ज़्यादा प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये राजस्थान स्किल्स प्रतियोगिता कराने पर भी विचार किया जा रहा है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में ऑटोमोटिव, रिटेल, स्वास्थ्य एवं लॉजिस्टिक्स पर तकनीकी सत्र आयोजित हुए।
- इस दौरान विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रीय कौशल परिषद, प्रशिक्षण प्रदाता, उद्योग संघ और कौशल विकास से संबंधित अन्य हितधारकों ने पैनल डिस्कस में भाग लेते हुए अपनी ज़रूरतों से अवगत कराया और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रमों में वांछित बदलाव करने के सुझाव दिये।
- उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इंडस्ट्री से कनेक्ट करने और युवाओं को 'ऑन जॉब ट्रेनिंग' कराकर व्यावहारिक ज्ञान देने पर बल दिया।
- कार्यक्रम में कौशल, उद्यमिता एवं नियोजन राज्य मंत्री अशोक चांदना ने अनांबिका जोशी एवं अशोक वर्मा को 'स्किल आइकन' के रूप में सम्मानित किया और प्रशिक्षण पूरा करने वाले 7 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के 'ऑफर लेटर' सौंपे।

मुख्यमंत्री ने ई-व्हीकल पॉलिसी को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (आरईवीपी) को मंज़ूरी दे दी। साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिये प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिये 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी।
- घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी का पुनर्भरण किये जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिये एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हज़ार रुपए प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हज़ार रुपए प्रति वाहन दिया जाएगा।
- प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है।
- इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीज़ल-पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

राजीविका की महिलाओं के जैविक उत्पादों का होगा प्रमाणीकरण

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2022 को राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिये राजीविका और राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू के तहत राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाएगा।
- राजीविका द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आठ ज़िलों के 19 ब्लॉक के 353 गाँवों में 2780 हेक्टेयर में जैविक खेती की जाएगी।
- महिला किसानों के जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण होने से प्रमाणित जैविक उत्पादों का विपणन करने में आसानी होगी। इससे इन जैविक उत्पादों की उत्पादक महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की राह प्रशस्त होने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।
- राजस्थान बीज एवं प्रमाणीकरण संस्था स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जैविक खेती व प्रमाणीकरण में तीन वर्ष तक सहयोग प्रदान करेगी।

कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

26 मई, 2022 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 में लोकहित में संशोधन करते हुए नए प्रावधान शामिल किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत स्थापित होने वाली प्रथम 100 मिलेट्स प्रसंस्करण इकाईयों को पात्र परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रुपए प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा, लेकिन ऐसी परियोजना जिनमें 40 लाख रुपए की अधिकतम सीमा से अधिक अनुदान देय है, उनमें निर्धारित अनुदान दर 25 प्रतिशत पर अनुदान देय होगा।
- अनुदान के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिये 23 फरवरी, 2022 के बाद आयोजित सभी डीएलएससी एवं एसएलएससी में स्वीकृत होने वाली सभी परियोजनाओं पर यह प्रावधान लागू होगा।

नोट :

- राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत स्थापित होने वाली इकाइयों पर अनुदान मिशन अवधि अथवा वर्ष 2023-24 या 100 इकाईयाँ स्थापित होने की अवधि, जो भी पहले हो, तक देय होगा। मिशन में निर्धारित इकाइयों का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद सभी लंबित आवेदनों पर अनुदान की दर नीति, 2019 के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।
- इसी प्रकार सभी श्रेणी (कृषक, उनके संगठन एवं इनके अतिरिक्त अन्य पात्र व्यक्ति) के आवेदकों को बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिये अनुदान 50 प्रतिशत अधिकतम एक करोड़ रुपए तक देय होगा।
- यह अनुदान लहसुन के लिये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बाराँ, अनार के लिये बाड़मेर एवं जालौर, संतरे के लिये झालावाड़ एवं भीलवाड़ा, टमाटर और आँवले के लिये जयपुर, सरसों के लिये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई-माधोपुर ज़िलों में स्थापित होने वाली इकाइयों को देय होगा। यह अनुदान मिशन अवधि अथवा वर्ष 2023-24, जो भी पहले हो तक के लिये देय होगा।
- जोधपुर संभाग में ज़ीरा व ईसबगोल के निर्यात आधारित प्रथम दस प्रसंस्करण इकाइयों को पूँजीगत अनुदान लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 करोड़ रुपए का अनुदान देय होगा। यह अनुदान भी मिशन अवधि अथवा वर्ष 2023-24, जो भी पहले हो, तक के लिये देय होगा।
- मिशन के तहत स्थापित होने वाली ज़ीरा एवं ईसबगोल की इन इकाइयों के लिये अनुदान की प्रक्रिया का निर्धारण अलग से किया जाएगा। मिशन में निर्धारित इकाइयों का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद सभी लंबित आवेदनों पर अनुदान की दर नीति, 2019 के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

राज्यपाल ने किया 'शिखर पर्व' का शुभारंभ एवं 'हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी' का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू स्थित राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 'शिखर पर्व' का शुभारंभ और 'शिखर पर्व' के अंतर्गत लगाई गई 'हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी' का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- 'हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी' में 20 कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है।
- पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि धरोहर संरक्षण के साथ उससे जुड़े कला सरोकारों के तहत इन चित्रों का प्रदर्शन किया गया है।
- उन्होंने बताया कि 'धरोहर आर्ट कैंप' और कोविड के दौर मेंघर पर रहते हुए इन कलाकृतियों का देश के विभिन्न राज्यों के चित्रकारों द्वारा सृजन किया गया था। इनका इससे पहले भी विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदर्शित कलाकृतियों में कलाकारों ने स्थान विशेष के रंग-स्थापत्य के साथ रेखाओं से सौंदर्य का विरल संसार सिरजा है। इनमें मंदिर, महल, मस्जिद, बावड़ियों, पहाड़ी क्षेत्र में बनी इमारतों के स्थापत्य, उनके सौंदर्य को कलाकारों ने अपनी कला-दृष्टि से जीवंत किया है।

मोरध्वज की नगरी को बनाया जाएगा पर्यटन नगरी

चर्चा में क्यों ?

27 मई, 2022 को राजस्थान सरकार ने राज्य के करौली ज़िले में राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मोरा में विकास कार्य और ऐतिहासिक स्थलों के रखरखाव के लिये पौने दो करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्य के लिये सरकार ने पुरातत्त्व विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि गढ़मोरा की पर्यटन विकास समिति विगत दो दशकों से इस ऐतिहासिक स्थल के स्वरूप को सँवारने के लिये लगातार प्रयास करती रही है।
- किले व महल का जीर्णोद्धार होने से राजा मोरध्वज नगरी का वैभवशाली एवं गौरवमयी इतिहास पुनरुज्जीवित हो सकेगा, साथ ही ऐतिहासिक धरोहर को जीर्ण-शीर्ण होने से बचाया जा सकेगा और इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

एसएमएस स्टेडियम में लोकार्पण व खिलाड़ी सम्मान समारोह

चर्चा में क्यों ?

29 मई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, नवीनीकृत सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ और बैडमिंटन इंडोर हॉल का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ओलंपिक और पैरा-ओलंपिक में राजस्थान के पदक विजेताओं तथा एशियन गेम्स, 2022 और कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 में क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
- इसके अलावा समारोह में मुख्यमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को अनुदान राशि देने के लिये ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजकीय सेवाओं में नियुक्तियाँ दी गई हैं, साथ ही खिलाड़ियों के लिये 2 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
- उन्होंने बताया कि ओलंपिक, पैरा-ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं के साथ अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्डीज को स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने ओलंपिक और पैरा-ओलंपिक पदक विजेताओं को 25-25 बीघा नि:शुल्क भूमि आवंटित करने तथा गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्डीज को मिलने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाने की घोषणा भी की।

जैसलमेर में भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2022 को अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के एमडी और सीईओ विनीत एस. जैन ने बताया कि एजीईएल की सहायक कंपनी अडाणी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड (एएचईजेओएल) ने जैसलमेर में पवन व सौर ऊर्जा के मेल वाला 390 मेगावाट का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, जो देश में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है।

प्रमुख बिंदु

- नए संयंत्र का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ बिजली खरीद समझौता (पीपीए) है, जिसमें टैरिफ 2.69 रुपए प्रति किलोवाट है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर औसत बिजली खरीद लागत (APPC) से काफी कम है।
- इस संयंत्र के सफलतापूर्वक चालू होने के साथ अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) की परिचालन क्षमता 5.8 गीगावाट हो गई है। यह एजीईएल के 20.4 गीगावाट के कुल नवीकरणीय पोर्टफोलियो को 2030 तक 45 गीगावाट क्षमता के अपने विज़न को पूरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।
- विनीत एस. जैन ने बताया कि सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से एकीकृत हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र उत्पादन अंतर को हल करके अक्षय ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग करता है और बढ़ती बिजली की माँग को पूरा करने के लिये एक अधिक विश्वसनीय समाधान प्रदान करता है।
- यह परियोजना अडानी ग्रीन में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा पहली निर्माण सुविधा का एक हिस्सा है।

नोट :

नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के प्रस्ताव को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में 250 कमरों वाले 'नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर' के निर्माण और संचालन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- अशोक गहलोत ने दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राजस्थान के अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने के लिये यह बड़ा निर्णय लिया है।
- उन्होंने बताया कि दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 330 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्टल बनने से दिल्ली में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और कैरियर काउंसिलिंग लेकर भविष्य सँवारने वाले राजस्थान के अल्प आय वर्ग के 500 विद्यार्थियों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2022-23 में दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर खोलने की घोषणा की थी।

नोट :